



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112 ]

No. 112]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2003/वैशाख 11, 1925  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2003/VAISAKHA 11, 1925

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2003

**विषय :—विशेष जमा योजना**

सं एफ 5(6)-ईसीबी एंड पी आर/2003.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. एफ. 16(1)-पीडी/75 दिनांक 30 जून, 1975 के पैरा 10 के संदर्भ में गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता तथा उपदान निधियों से संबद्ध विशेष जमा योजना जिसे 2 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं. एफ. 15(23)-पीडी/94 द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों पर 30 जून, 2003 तक विस्तारित किया गया था, उसे पुनः 1 जुलाई, 2003 से उस अवधि तक, जैसा कि सरकार निम्नलिखित संशोधित शर्तों के अनुसार अधिसूचित करे, और बढ़ाया जाता है :

**निवेश :** दिनांक 30 जून, 2003 के बाद विशेष जमा योजना में किसी नए निवेश की अनुमति नहीं होगी।

**ब्याज :** ब्याज के कारण योजना की समूह निधि में जमाराशियां वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 5 (18)-ईसीबी/2001 दिनांक 6 मार्च, 2003 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I के खण्ड-1 में दिनांक 7 मार्च, 2003 को प्रकाशित किया गया है, द्वारा जारी वृद्धि जमा रकमों से संबंधित निवेश के पैटर्न के अनुसार निवेशित की जाएंगी।

**जमाराशियों की वापसी :** जमाराशियों की वापसी उनके पुनर्भुगतान से पहले देय होने पर, इस संबंध में न्यासी अथवा किसी पात्र निधि के प्रशासक द्वारा जमा कार्यालय में, जहां कि जमाराशियां रखी गयी हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित दशा में की जाएगी :—

- (क) कर्मचारियों द्वारा निधि में दावों के निपटान के संबंध में निधि के निवेश के निपटान तथा वसूली के परिणामस्वरूप संबद्ध स्थापना की समाप्ति; अथवा
- (ख) किसी पात्र निधि द्वारा अनिवार्य भुगतान करना;
- (ग) संबद्ध स्थापना जो बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा विनियमित भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियों के साथ संपन्न बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान निश्चित करे अथवा इन कंपनियों/एलआईसी से वार्षिकी की खरीद हेतु।

**पुनर्भुगतान :** केन्द्र सरकार इस योजना के तहत योजना के अंशधारकों के लिए दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, अंशधारकों के साथ परामर्श करके निर्धारित की गयी राशि अथवा परिपक्वता के अनुसार जारी करके बकाया शेष राशि का पुनर्भुगतान कर सकती है।

शशांक सक्सेना, संयुक्त निदेशक (एसई एण्ड ईसीबी-II)

## MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2003

**Subject :—Special Deposit Scheme**

**No. F. 5(6)-ECB&PR/2003.**—It is hereby notified that in terms of paragraph 10 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. 16(1)-PD/75 dated 30th June, 1975 the Special Deposit Scheme for non-Government provident, superannuation and gratuity funds which was extended upto 30th June, 2003 vide notification No. F. 15(23)-PD/94 dated 2nd March, 1998 on terms and conditions specified from time to time is further extended with effect from 1st July, 2003 till such time as the Government may notify on the following modified terms and conditions :

**Investments :** No new investment in the Special Deposit Scheme shall be allowed after 30th June, 2003.

**Interest :** The accretions in the corpus of the scheme on account of interest shall be invested as per the pattern of investment for incremental accretions issued by Ministry of Finance vide Notification No. 5(18)-ECB/2001 dated 6th March, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section-1 published on 7th March, 2003.

**Refund of Deposits :** Refund of deposits, before their repayment becomes due, will be allowed, on application, made in this behalf, by the trustees or administrator of an eligible fund to the deposit office at which the deposit is held, in the event of :—

- (a) the winding up of the related establishment followed by the disposal and realisation of the fund's investment for settlement of the claims on the fund by the employees; or
- (b) obligatory payments by an eligible fund;
- (c) the related establishment deciding to make payments under the scheme of Insurance entered into with insurance companies regulated by the Insurance Development and Regulatory Authority (IRDA) including Life Insurance Corporation of India (LIC) or for purchase of annuities from these companies/LIC.

**Repayment :** Central Government may make repayment of the outstanding balance under the Scheme through issue of dated Government securities to the subscribers of the Scheme for such amount and maturity as it may decide, in consultation with the subscribers.

SHASHANK SAKSENA, Jt. Director (SE & ECB-II)